भारतसरकार

कौशलविकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकितप्रश्न संख्या 148

उत्तरदेने की तारीख 1 दिसंबर, 2025

सोमवार, 2025/10 अग्रहायण,1947 (शक)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजनाएँ

148. श्री दर्शन सिंह चौधरीः
श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नव स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) त्रिपुरा राज्य सहित आईटीआई के उन्नयन की राष्ट्रीय योजना के लिए कुल कितना बजट आबंटित किया गया है; और

(ग) क्या विकास के लिए मौजूदा आईटीआई और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को किस प्रकार एकीकृत किया जाएगा?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) महोदय, मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन (पीएम सेतु) योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. आईटीआई और एनएसटीआई में प्रशिक्षण प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार अवसंरचना और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-अनुरूपदीर्घावधिक और अल्पावधिकपाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. मांग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोजगार परिणामों के लिए उद्योग संपर्क को सुदृढ़ करना; और

v. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना।

इस योजना के दो घटक हैं:

i. घटक I - 1,000 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (200 हब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 800 स्पोक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का हब और स्पोक मॉडल में उन्नयन। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों के साथ उन्नत किया जाएगा।

ii. घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि, जिसमें वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

(ख) इस स्कीम का कुल अनुमानित व्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें पांच वर्ष की अवधि के दौरान केंद्र सरकार (₹30,000 करोड़), राज्य सरकारें (₹20,000 करोड़), और उद्योग भागीदारों(₹10,000 करोड़) का अंशदान होगा।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (त्रिपुरा सहित) के लिए बजटीय आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित है, जो उद्योग-सहयोग के लिए उनकी रुचि, तत्परता और क्षमता को दर्शाता है। निधियों का संवितरण प्रत्येक क्लस्टर के लिए एआईपी द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) के अनुमोदन से जुड़ा होगा, जिसमें अवसंरचना,उपकरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन और प्रशिक्षण परिणामों का विवरण दिया जाएगा।

(ग) इस योजना में भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत कौशल के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण, उद्योग-संचालित कौशल कार्यक्रमों और वैश्विक पद्धतियों से परिचय करवाने पर ध्यान केंद्रित करना है। ये केंद्र आईटीआई के प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करेंगे, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। ये केंद्र देश भर के आईटीआई के लिए उपलब्ध होंगे और प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, योजना के दिशानिर्देशों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रोंकी भागीदारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संस्थानों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

*****